



## भूमि सम्मान 2023

### प्रलिस के लयः

[डजिटल इंडया भूमि अभलिख आधुनकीकरण कार्यक्रम, आधार कार्ड, वशिषिट भूखंड पहचान संख्या, ब्लॉकचेन-आधारति परणाली, भौगोलकि सूचना परणाली](#)

### मेन्स के लयः

भूमि अभलिखों के डजिटलीकरण से जुडी चुनौतियाँ

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत की राष्ट्रपति](#) ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजति एक समारोह में "भूमि सम्मान" 2023 प्रदान कया ।

## भूमि सम्मान:

- 'भूमि सम्मान' [डजिटल इंडया भूमि रिकॉर्ड आधुनकीकरण कार्यक्रम \(Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP\)](#) के कार्यानवयन में राज्यों और जिलों की उपलब्धियों को पहचानने तथा प्रोत्साहति करने के लयिकेंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रतिष्ठति पुरस्कार योजना है ।
- यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ प्रदान कया जाता है जिनोंने DILRMP के मुख्य घटकों की परपूरणता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कया है, जैसे:
  - भूमि अभलिखों का कंप्यूटरीकरण
  - भूसंपत्ति मानचित्रों का डजिटलीकरण
  - पाठ्यचर्या और स्थानकि डेटा का एकीकरण
  - आधुनकि तकनीक का उपयोग कर सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण
  - पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण
  - पंजीकरण और भूमि अभलिखों के बीच अंतर-संचालनीयता

नोट: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत [डजिटल इंडया भूमि रिकॉर्ड आधुनकीकरण कार्यक्रम](#) (तत्कालीन राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनकीकरण कार्यक्रम) को 1 अप्रैल, 2016 से केंद्र द्वारा 100% वतितपोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संशोधति और परविरतति कया गया था ।

## भूमि अभलिखों के डजिटलीकरण से लाभ:

- पारदर्शति और जवाबदेही: भूमि अभलिखों के डजिटलीकरण से लेन-देन में पारदर्शति बढ़ती है, जसिसे भूमि से संबंधति अनैतिक और अवैध गतविधियों की गुंजाइश कम हो जाती है ।
- आपदा प्रबंधन: डजिटल रिकॉर्ड बाढ़ और आग जैसी प्राकृतकि आपदाओं के प्रति अधिक अनुकूल हैं जसिसे भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेजों को नुकसान से बचाया जा सकता है ।
- भूमि पारसल पहचान संख्या: [आधार कार्ड](#) के समान, [डजिटल इंडया भूमि सूचना प्रबंधन परणाली](#) के तहत प्रदान की गई [वशिषिट भूमि पारसल पहचान संख्या](#) कुशल भूमि उपयोग की अनुमति देती है तथा नई कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण एवं कार्यानवयन को सक्रम बनाती है ।
- भूमि विवादों का समाधान: स्वतंत्र एवं सुवधिजनक तरीके से भूमि संबंधी जानकारी तक पहुँचस्वामतिव और भूमि-उपयोग विवादों को हल करने में सहायता करती है जसिसे प्रशासन और न्यायपालकि पर बोझ कम होता है ।

## भूमिअभिलेखों के डजिटिलीकरण से संबंधति चुनौतियाँ:

- **खंडति भूमि रिकॉर्ड:** भारत में भूमि रिकॉर्ड वभिनिन स्तरों पर अनेक प्राधकिरणों द्वारा तैयार कथि जाते हैं जसिमें गाँव, ज़िला और राज्य शामिल हैं।
  - इन अभिलेखों के बीच **एकरूपता एवं एकीकरण की कमी** उन्हें केंद्रीकृत और डजिटिलीकृत करने में कठनिाइयाँ उत्पन्न कर सकती है।
- **तकनीकी अवसंरचना एवं कनेक्टविटी:** डजिटिलीकरण के लथि **हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टविटी** सहति पर्याप्त तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता होती है।
  - ग्रामीण कषेत्रों में जहाँ अधकिंश भूमि स्थति है, वहाँ बुनयिदी ढाँचे की उपलब्धता सीमति हो सकती है, जसिसे डजिटिलीकरण प्रक्रथि में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता:** भूमिअभिलेखों में संवेदनशील व्यक्तगित और संपत्ति-संबंधी जानकारी होती है।
  - डजिटिलीकरण में डेटा की **सुरक्षा और गोपनीयता** सुनिश्चिति करना, अनधकृत पहुँच तथा दुरुपयोग को रोकना भी महत्त्वपूर्ण है।

## आगे की राह

- **ब्लॉकचेन-आधारति भूमिअभिलेख:** भूमिअभिलेखों को संग्रहण और प्रबंधन के लथि **ब्लॉकचेन-आधारति प्रणाली** लागू करना।
  - **ब्लॉकचेन की वकेंद्रीकृत तथा अपरविर्तनीय प्रकृति** पारदर्शति सुनिश्चिति करती है, धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के साथ भूमि के हस्तांतरण में वशिवास को बढ़ावा देती है।
- **ड्रोन सर्वेक्षण एवं GIS मैपिंग:** भूमिपारसल का सटीक सर्वेक्षण करने के लथि उच्च-रजिऑल्यूशन वाले कैमरों और लडार तकनीक से लैस ड्रोन का उपयोग करना।
  - भूमिअभिलेख का एक गतशील और वास्तवकि समय प्रतनिधित्व के लथि **भौगोलकि सूचना प्रणाली (GIS) मैपिंग** के साथ डेटा को एकीकृत करना।
  - भूमि रिकॉर्ड के करथिानवयन और रथिल-टाइम नरिूपण के लथि **भौगोलकि सूचना प्रणाली (Geographic Information System-GIS) मैपिंग** के साथ डेटा को एकीकृत करना।
- **मानकीकरण और अंतर-संचालनीयता:** वभिनिन वभिगों और प्रणालथियों में भूमि रिकॉर्ड की अनुकूलता और नरिबाध एकीकरण सुनिश्चिति करने के लथि समान डेटा मानक एवं प्रारूप स्थापति करना।
  - इससे डेटा साझाकरण और पुनरप्राप्त अधकि प्रभावी होगी।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. स्वतंत्र भारत में भूमिसुधारों के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

- हदबंदी कानून पारविरकि जोत पर केंद्रति थे, न क व्यक्तगित जोत पर।
- भूमिसुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहिनों को कृषि भूमि प्रदान करना था।
- इसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की खेती, कृषि का प्रमुख रूप बन गई।
- भूमिसुधारों ने हदबंदी सीमाओं को कसि भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी।

उत्तर: (b)

**??????????:**

प्रश्न. कृषि वकिास में भूमिसुधारों की भूमिका की वविचना कीजथि। भारत में भूमिसुधारों की सफलता के लथि उत्तरदायी कारकों को चहिनति कीजथि। (2016)

**स्रोत: पी.आई.बी.**